# औद्योगिक विकास

पिछले दस वर्षों में इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, इटली और रूस को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस श्रेय के कई कारक हैं। भारत में आजादी से पहले और बाद में क्रमबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास हुआ है। एक स्पष्ट औद्योगिक नीति के साथ आर्थिक सुधार नीति तथा वर्तमान सरकार की संरक्षण नीति को इसका श्रेय दिया जा सकता है। एक नजर

# आत्मनिर्भरता की राह पर भारतीय उद्योग

अश्विनी महाजन, अर्थशास्त्री

डॉलर की बाजार कीमत के आधार पर भारत लगभग 4 खरब डालर, और क्रय शक्ति समता के आधार 13 खरब डालर से भी ज्यादा की जीडीपी के साथ, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले दस सालों में भारत इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, इटली और रूस को पछाड़ते हुए पांचवें क्रमांक पर पहुंचा है। लेकिन निर्माण और उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में मात्र 3.3 प्रतिशत हिस्सा ही रखता है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन जीडीपी की प्रगति में उद्योगों के योगदान की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान कहीं अधिक रहा और देश आयातों पर अत्यधिक निर्भर रहा।

## स्वतंत्रता के पहले के प्रयास

वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन के बाद कई नई कपड़ा और जूट मिलें देश में स्थापित हुईं। कोयले का उत्पादन बढ़ा, रेलवे का भी तेजी से विस्तार हुआ और लोहा तथा इस्पात उद्योग की नींव भी इसी दौरान रखी गई। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत के कारखानों में बने उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी। इंग्लैंड और अन्य देशों से आयात कम हुए और स्वयं विदेशी सरकार ने भी युद्ध के उद्देश्य से काफी सामान खरीदना शुरू कर दिया।

स्वदेशी आंदोलन के दबाव में कुछ चुनिंदा भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु आयात शुल्क लगाने के लिए सरकार राजी हो गई। इससे 1924 और 1939 के बीच कई उद्योगों को संरक्षण के कारण लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र, जूट, चीनी, कागज और माचिस उद्योगों का विकास हुआ। 1939 के द्वितीय विश्वयुद्ध ने भारतीय उद्योगों के साजो-सामान की मांग और तेजी से बढ़ाई। कई नए उद्योग लगे, जिन्हें 'वार बेबी' यानी युद्ध की संतानें भी कहा जाता था।

## आजादी के बाद औद्योगिक रणनीति

जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारत में औद्योगीकरण के नाम पर मात्र कुछ उद्योग ही थे, जिनमें अधिकांशतः उपभोक्ता वस्तु उद्योग ही थे। पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनरी, बड़े औद्योगिक प्लांट, बुनियादी और अन्यान्य प्रकार के पूंजीगत उद्योग भारत में नहीं थे। ऐसे में आजाद भारत में औद्योगिक विकास की नींव रखने के लिए सरकार ने एक रणनीति तैयार की। इसके तहत बड़े पूंजीगत उद्योग, मशीनों के निर्माण के लिए बड़े मशीन उद्योग, मूलभूत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, रसायन उद्योग आदि की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाए।

आजादी के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा भारी निवेश के बाद बड़ी संख्या में लोहा और इस्पात, रसायन, मशीनरी, सीमेंट, एल्युमीनियम, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली सरीखे मूलभूत उद्योग स्थापित हुए। लेकिन कुल मेन्युफैक्चरिंग उत्पादन में वृद्धि बहुत सीमित थी। वर्ष 1950-51 और 1970-71 के बीच मेन्युफैक्चरिंग की वृद्धि दर मात्र 5.6 प्रतिशत रही। 1970-71 और 1980-81 के बीच तो यह केवल 4 प्रतिशत ही थी। प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने के कारण अंतरराष्ट्रीय वस्तु निर्यातों में भारत का हिस्सा 1950-51 में 2.1 प्रतिशत से घटता हुआ 1980-81 तक मात्र 0.4 प्रतिशत रह गया।

## 1991 के आर्थिक सुधार

1991 तक आते-आते ऐसी स्थिति आ गई कि आयातों और निर्यातों में बड़े अंतर के कारण भारत भुगतान संकट का जबरदस्त शिकार हो गया। हमें लेनदारों को आश्वस्त करने के लिए अपना सोना प्रतिभूति के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजना पड़ा। ऐसे में सरकार जिसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, ने कहा कि गलत नीतियों की वजह से देश का औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ है और उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण ही एकमात्र रास्ता है। विदेशी निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोलना ही आर्थिक सुधार कहलाने लगा। इस नीति के अंतर्गत डब्लूटीओ में हस्ताक्षर करते हुए देश की सीमाओं को न्यूनतम टैरिफ पर आयातों के लिए खोल दिया गया। गैर टैरिफ बाधाएं भी समाप्त कर दी गईं और विदेशी निवेश को भी खुली छूट दे दी गई। इससे देश की जीडीपी में मेन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 19 प्रतिशत से घटते हुए मात्र 16 प्रतिशत के करीब आ गया।

ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि नीतियों के अंतर्गत भारतीय उद्योग क्षेत्र को वापस लाने के प्रयास हुए लेकिन उनका सीमित लाभ ही मिला।

## संरक्षण की नीति पर जोर

वर्ष 2018 के बाजार में पहली बार संरक्षण की नीति आंशिक रूप से अपनाई गई। इससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उत्पादन तथा निर्यात दोनों बढ़े। 2020 की महामारी के दौरान सरकार ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए आत्मनिर्भर भारत नीति की शुरुआत की।

इस नीति के अंतर्गत उन तमाम वस्तुओं का उत्पादन अब देश में करने का प्रयास शुरू हुआ है, जो चीन से असमान और धोखाधड़ी की तरकीबों के कारण बाधित हुआ। सरकार द्वारा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के माध्यम से रसायन, एपीआई, मोबाइल फोन और अन्य टेलीकॉम तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर, वस्त्र एवं परिधान, कागज, खिलौने, साइकिल, मशीनरी, एलईडी, लैपटॉप, सेमी कंडक्टर इत्यादि समेत 15 उद्योगों को चुना गया। इससे उम्मीद की जा रही है कि उद्योगों को पुनः स्थापित किया जा सकेगा। इसके सुखद परिणाम के रूप में खिलौनों में आयात घटा है। निर्यातों में वृद्धि हुई है। मोबाइल फोनों का बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है। जिन उद्योगों में पीएलआई दी गई है, वहां बड़ी मात्रा में निवेश भी हो रहा है। इसके अलावा देश में प्रतिरक्षा के साजो-सामान के उत्पादन और निर्यात में भी बड़ी वृद्धि हुई है।

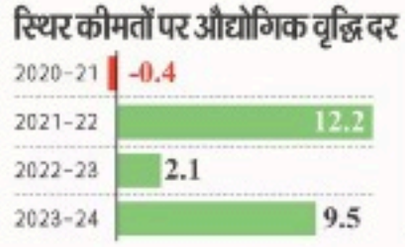




**9.5%**
औद्योगिक विकास दर रही, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार

### नीतियों का भी योगदान

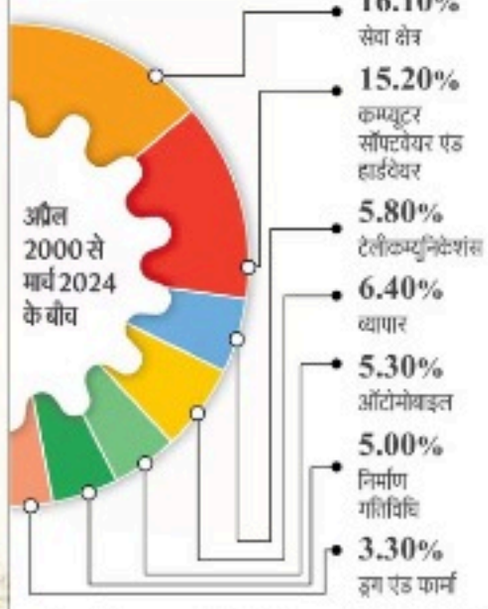

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के 1 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, वर्ष 2025-26 तक। गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु प्रमुख अग्रणी राज्य हैं। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स व कपड़ा उद्योगों में बढ़ता निवेश औद्योगिक क्षेत्र में तेजी का एक बड़ा कारण है। मेक इन इंडिया, पीएलआई योजनाएं, डीपीआईआईटी आदि योजनाएं आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं।

### निर्माण उपक्षेत्रों में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)




**8.2%**
रही सकल उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2024 में, यह साल में चार में से तीन तिमाहियों में 8 प्रतिशत अधिक रही

**4.5%**
महंगाई दर में कमी का अनुमान वित्त वर्ष 2025 में, आरबीआई के अनुसार

**2.35**
करोड़ हो जाएगी गिग कार्यबल में शामिल लोगों की संख्या, वर्ष 2029-30 तक बढ़कर

### विनिर्माण निर्यात में आई जबरदस्त तेजी

इन दिनों भारतीय विनिर्माण निर्यात में तेजी दर्ज होती देखी जा रही है। बीते वर्ष यह उल्लेखनीय उपलब्धि रही। आईबीईएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में 447.46 खरब डॉलर का वार्षिक निर्यात हुआ। यह 6.03 फीसदी की वृद्धि दर के साथ अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निर्यात आंकड़ा है। वित्त वर्ष 2022 में यह 422 अरब डॉलर था।